वर्ष 2030 तक सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित होंगे- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित लोक अभियोजकों की कार्यशाला को संबोधित किया

जयपुर, 9 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोक अभियोजक न्याय व्यवस्था की एक अहम कड़ी हैं, जो विधिक मामलों में राज्य के प्रतिनिधित्व के साथ ही न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में भी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बदलते कानूनों और न्यायिक दृष्टिकोणों के अनुरुप अधिकारियों का निरंतर प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिड़ला ऑडिटोरियम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग के लोक अभियोजकों एवं विशेष लोक अभियोजकों की कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास व पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा भी मौजूद रहे।

सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति तक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो। इसी लक्ष्य के साथ राज्य सरकार प्रदेश में संवेदनशील, प्रभावी एवं जनोन्मुखी कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री शनिवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजकों एवं विशेष लोक अभियोजकों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदलते कानूनों और न्यायिक दृष्टिकोणों के अनुरूप, अधिकारियों का निरंतर प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह कार्यशाला लोक अभियोजकों को नए आपराधिक कानूनों, साइबर कानूनों तथा दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनों के प्रति अधिक जागरूक, संवेदनशील एवं दक्ष बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तीनों नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस और अभियोजन को इन कानूनों की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के समस्त पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं तथा वर्ष 2030 तक समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह हमारी सरकार डिजिटल अरैस्ट सहित, अन्य साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की भी स्थापना करने जा रही है। राज्य सरकार साइबर अपराधों के एआई आधारित विश्लेषण तथा साइबर हैल्पलाइन कॉल सेंटर की व्यवस्था करेगी।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के ध्येय के साथ कार्य कर रही है।

इस अवसर पर महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राघवेन्द्र काछवाल सहित विधि एवं विधिक कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में लोक अभियोजकगण व अधिवक्तागण मौजूद रहे।

पंजाब के मंत्री संजीव अरोडा को ईडी ने गिरफ्तार किया

चंडीगढ़ , 09 मई । पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ के बाद चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम ने यह कार्रवाई 157 करोड़ की फर्जी बिक्री तथा फर्जी शैल कंपनियों के माध्यम से पैसों की लेन-देन के आधार पर की है। मंत्री की गिरफ्तारी के साथ ही पंजाब की राजनीति गरमा गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री संजीव अरोड़ा के समर्थन में आ गए हैं। वहीं, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा अकाली दल ने आम आदमी पार्टी (आप) का विरोध किया है।

ईडी की टीमों ने पिछले 20 दिन में शनिवार को दूसरी बार छापा मारा। ईडी की टीमों ने आज सुबह कार्रवाई शुरू की। दोपहर करीब एक बजे चंडीगढ़ आवास पर पंजाब के ऊर्जा एवं उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद ईडी ने कागजी कार्रवाई पूरी की।

अनिल अंबानी समूह के 17 ठिकानों पर छापा

सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में यह कार्यवाही की है

नई दिल्ली, 09 मई । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अनिल अंबानी समूह से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामलों में शनिवार को मुंबई में 17 स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। यह कार्रवाई रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड तथा उनके निदेशकों के खिलाफ दर्ज मामलों में की गई।

सीबीआई के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम को हजारों करोड़ रुपये के कथित नुकसान से जुड़े मामलों की जांच जारी है। यह छापेमारी 08 मई को मुंबई स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। जांच एजेंसी ने निदेशकों के

- **सीबीआई ने बताया कि रेड में कई महत्वपूर्ण एवं आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है।**

आवासीय परिसरों के अलावा उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी तलाशी ली, जिनके खातों का कथित तौर पर बैंक धनराशि के डायवर्जन और लेन-देन के लिए उपयोग किया गया था।

एजेंसी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कई मध्यस्थ कंपनियां एक ही पते से संचालित हो रही थीं, जिससे लेन-देन के नेटवर्क और धनराशि के उपयोग को लेकर संदेह और गहरा हुआ है। जब दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, संबंधित कंपनियों और मध्यस्थ इकाइयों के बीच संबंधों की पड़ताल की जा रही है। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि कथित तौर पर लिए गए ऋण का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य माध्यमों में किया गया या नहीं। जांच एजेंसी ने बताया कि अनिल अंबानी समूह से जुड़े इन मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में की जा रही है। मामले में आगे भी कई लोगों से पूछताछ और अतिरिक्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

यूक्रेन युद्ध का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पश्चिम के संदर्भ में परिभाषित किया, चाहे प्रतिस्पर्धा, प्रशंसा या संघर्ष के माध्यम से किया हो। लेकिन आज, वह पुराना ढांचा फीका पड़ रहा है। पश्चिम स्वयं विखंडित और अनिश्चित दिखाई देता है, जिससे रूस को कोई स्पष्ट बाहरी संदर्भ बिंदु नहीं मिलता। क्रेमलिन ने इसके स्थान पर एक प्रेरक आंतरिक दृष्टि पेश करने में संघर्ष किया है।

चौथा कारक राज्य और समाज के बीच पुराने सामाजिक अनुबंध का पतन है। पहले, कई रूसी सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बदले बर्दाश्त कर लेते थे। वह संतुलन अब मौजूद नहीं है। राज्य धीरे-धीरे दैनिक जीवन में निगरानी, सेंसरशिप और वैचारिक नियंत्रण के माध्यम से हस्तक्षेप करता है, जबकि भविष्य के प्रति कोई आशावाद नहीं देता।

यह स्थिति शतरंज के खिलाड़ियों द्वारा "जुगज़वांग" कहा जाता है - ऐसी स्थिति जहां, हर संभव चाल स्थिति को और खराब कर देती है। पुतिन दमन बढ़ा सकते हैं या नियंत्रण बनाए रखने के लिए विदेशों में टकराव बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रत्येक कदम से रूस की स्थिरता और अनिश्चितता गहराती है।

प्रणाली कई वर्षों तक टिक सकती है, क्योंकि अधिनायकवादी शासन अक्सर डर और जड़ता पर जीवित रहते हैं। फिर भी पुतिन के लिए गहरी चुनौती अब केवल सत्ता बनाए रखने की नहीं है। यह विश्वास बहाल करने की है कि उनका शासन अभी भी रूस के लिए एक व्यवहार्य भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है।

क्या राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वहीं वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पर विरोध और धरने हो रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, बैठक की मुख्य घटना वीडी सतीशन का इस्तीफा देने की धमकी देना और अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कोई पद न लेने की घोषणा करना रही।

बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उन्होंने कड़ी मेहनत की, हर गाँव और ज़िले में जाकर पार्टी के लिए काम और प्रचार किया, जबकि वेणुगोपाल दिल्ली में बैठे और बिना काम किए सत्ता के लाभ का आनंद उठा रहे थे और अब कह रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।

अपुष्ट सूत्रों के अनुसार, वेणुगोपाल ने भी अपनी कमर कस ली है और कहा है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि सतीशन मुख्यमंत्री न बनें।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी और राज्य में सतीशन को जबरदस्त समर्थन प्राप्त है और राहुल गांधी को सूझबूझ और विवेक के आधार पर निर्णय लेना होगा, अन्यथा पार्टी को गंभीर नुकसान हो सकता है।

यह भी बताया गया है कि वायनाड,जो पहले राहुल और अब प्रियंका का लोकसभा क्षेत्र है, में सतीशन का काफी समर्थन है और आईयूएमएल भी सतीशन के बहुत करीब है। उन्होंने भी राहुल गांधी पर दबाव डाला है। यह मुद्दा अभी भी बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है।

पार्टी केवल एक राज्य में जीती है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक कोई समाधान या निर्णय नहीं किया जा सका है।

नौ साल पहले मारे गए भाजपा कार्यकर्ता के परिवार से मिले प्रधानमंत्री

प्र.मंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मारे गए सौमित्र घोषाल के परिवार से मुलाकात की

बारुईपुर, 09 मई। पश्चिम बंगाल में साल 2017 में हुई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता की हत्या के मामले में एक बार पुन: न्याय की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मृतक सौमित्र घोषाल के परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया।

सौमित्र घोषाल, जो दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर के दक्षिण गड़िया इलाके के निवासी थे। उनकी 2017 में दिनदहाड़े पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजनीतिक वजहों से उनकी हत्या कर शव को एक सुपारी बागान में लटका दिया गया था। घटना के बाद लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिल सका। अब राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद पीड़ित परिवार को एक बार फिर उम्मीद जगी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद परिवार के सदस्यों

- **मृतक की मां बनलता घोषाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है।**

ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस बार उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।

मृतक की मां बनलता घोषाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन से उन्हें नई उम्मीद मिली है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा भाजपा से जुड़ा था और इसलिए उसे निशाना बनाया गया।

वहीं, परिवार की अन्य सदस्यों ने भी कहा कि वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष करने के बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि हालात बदलेंगे।

लोगों ने भी प्रधानमंत्री के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इतने साल बाद भी मामले को याद रखना और परिवार से मिलना बड़ी बात है, जिससे न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है

मंगलवार को शपथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैठक भी होगी, जिसमें एनडीए का नेता चुना जाएगा।

सरमा ने कहा, दोपहर 12 बजे, एनडीए के नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जैसे ही राज्यपाल अनुमति देंगे, सरकार बनाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगा।" सरमा ने आगे कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में असम में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। बहुत से उद्योगपतियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा, सत्राधिकारों और वैष्णव धार्मिक प्रमुखों के साथ-साथ, भाजपा और बूथ समितियों के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला व केन्द्रीय मंत्रियों ने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 09 मई। पराक्रम और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराणा प्रताप की जयंती पर नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और राष्ट्रधर्म के जीवंत प्रतीक थे, जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की रक्षा एवं स्वाभिमान की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और त्याग के सर्वोच्च प्रेरणास्रोत महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि, धर्म और संस्कृति की रक्षा तथा इनके स्वाभिमान की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले, अदम्य शौर्य और अटूट स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर नमन।

भाजपा को रोकने के लिये वामदलों का सहयोग ले सकती हूँ- ममता

कोलकाता, 09 मई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर

- **ममता बनर्जी के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई।**

अपने बयान से राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यदि जरूरत पड़ी तो वे वाम दलों से सहयोग लेने में भी कोई आपत्ति नहीं करेंगी।

ममता बनर्जी ने यह बयान कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास के निकट आयोजित रवीन्द्रनाथ टैगोर जयंती समारोह के दौरान दिया।

तमिलनाडु में विजय के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ

चेन्नई, 09 मई । तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कई दिनों से चला आ रहा सियासी सस्पेंस आखिरकार समाप्त हो गया है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्टी कझगम (टीवीके) को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत मिल गया है। विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) ने शनिवार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी, जिसके बाद विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।

चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों का समर्थन विजय को देने की घोषणा की। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी अपने-अपने दो विधायकों का समर्थन दिया। इन समर्थन पत्रों के बाद टीवीके के पक्ष में कुल संख्या 117 तक पहुंच गई थी। इसके बाद पूरे राज्य की निगाहें

- **वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद विजय के पास 120 विधायकों का समर्थन हैं, वे जल्दी ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।**

वीसीके पर टिक गई थीं। शनिवार शाम हुई पार्टी की अहम बैठक में टीवीके को समर्थन देने पर सहमति बनी। वीसीके ने बिना किसी शर्त के विजय को समर्थन पत्र सौंप दिया। पार्टी के दो विधायकों के समर्थन के बाद टीवीके के समर्थन में कुल संख्या 118 हो गई, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का आंकड़ा है।

इस बीच राज्य की राजनीति में एक और मोड़ तब आया, जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने भी समर्थन दे दिया।

अब विजय जल्द ही राज्यपाल से दोबारा मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

एसएमएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करीब सवा तीन बजे आठवीं मंजिल पर पहुंच कर नितिन ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। घटना स्थल पर केवल एक स्मार्ट फोन और लैपटॉप मिला है। हॉस्टल स्टाफ का कहना है कि छात्र लैपटॉप बैग में रस्सी लेकर आया था।

प.बंगाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कीर्तनिया। इन पांच मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित, अन्य शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शपथ ली।

पश्चिम बंगाल कैबिनेट में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार 44 है, जिसमें अभी 39 और मंत्रियों को शामिल करने की जगह है।

'युवा को नौकरी देने की बजाय लाठिया दी जा रही हैं'

राहुल गांधी ने पटना में बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की

नई दिल्ली, 09 मई । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनने के बजाय, सरकार उन पर बल प्रयोग कर रही है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस घटना से जुड़ा लगभग एक मिनट का एक वीडियो साझा किया, जिसमें पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे छात्रों

- **राहुल गांधी ने एक्स पर लाठीचार्ज का वीडियो भी पोस्ट किया।**

पर लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट में कहा कि अपने रोजगार के अधिकार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बिहार पुलिस ने बेरहमी का व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारों के पास बेरोजगार युवाओं के सवालों का जवाब केवल लाठीचार्ज और दमन है।

राहुल गांधी ने लिखा कि आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सबसे अधिक असर बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहा है। लाखों युवा डिग्री और योग्यता हासिल करने के बाद भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आती। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब युवा अपने अधिकार और रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तब उन्हें नौकरी देने के बजाय लाठियां दी जाती हैं।

भाजपा बनी ''बंगालार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

श्यामा प्रसाद के साथ कश्मीर गए थे। इसके पहले, श्यामा प्रसाद केन्द्र सरकार में उद्योग मंत्री बन गये थे।

दुर्भाग्यवश, इस विरोध यात्रा के दौरान श्यामा प्रसाद की कश्मीर की जेल में मृत्यु हो गई और इस बात की गहरी आशंका है कि उनकी जेल में हत्या कर दी गई थी। भाजपा के मास्टर ऑफ़ सेरेमनी ने वास्तव में इस घटना का उल्लेख किया और कहा कि डॉ. मुखर्जी की हत्या वास्तव में हुई थी।

माखन लाल सरकार को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री ने सरकार को एक शॉल भेंट किया। शॉल पहनाते समय प्रधानमंत्री ने 97 वर्षीय माखन लाल के पैर छूकर उनका सम्मान भी किया। यह एक भावनात्मक क्षण बन गया।

सन् 1951 की विरोध यात्रा के बाद माखन लाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 1950 के दशक की शुरुआत में दिल्ली की अदालत में उनके मुकदमे के दौरान, न्यायाधीश ने गिरफ्तारी का कारण पूछा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक ऐसा गीत गाया था, जिसे आपत्तिजनक माना गया।

उत्साही माखन लाल ने एक जोशीला देशभक्ति गीत गाया था, और यह बात जानकर, दिल्ली की अदालत के न्यायाधीश ने युवक से अदालत में ही वह गीत गाने को कहा।

अदालत में गीत सुनने के बाद, न्यायाधीश ने आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस तुरंत उन्हें रिहा करे, सिलीगुड़ी बंगाल में उनके घर के लिए प्रथम श्रेणी टिकट का आयोजन करे और यात्रा के दौरान आकस्मिक खर्चों के लिए 100 रुपये की राशि प्रदान करे। भाजपा ने इस पूरी घटना को अपने शुरुआती दिनों में वैधता हासिल करने के संघर्ष के रुप में बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया तथा इस बात का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा।

कई अन्य मायनों में यह समारोह एक नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गया।

यह राज्य में भाजपा के "बंगालीपन" का एक बड़ा शो बन गया। पार्टी के बंगाली सांस्कृतिक झुकाव के इस जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का उद्देश्य ममता बनर्जी के इस आरोप का खंडन करना था कि भाजपा बंगाल विरोधी है और बंगाली पहचान से उसका कोई संबंध नहीं है।

सबसे पहले, शपथ ग्रहण की तारीख जानबूझकर 25 बैसाख चुनी गई, जो रबींद्रनाथ टैगोर की जयंती है, और टैगोर बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा की गहरी पहचान हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मंच पर लगे एक बड़े चित्र के सामने पुष्प अर्पित करके कवि को श्रद्धांजलि दी।

पार्टी ने बंगाल की सांस्कृतिक विविधता का एक अद्भुत प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें आदिवासी लोक नृत्यों से लेकर दुर्गा पूजा के ढोल की थाप शामिल थी। सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक प्रभाव को रेखांकित करने के लिए, "झाल मुड़ी" की 25 स्टॉल लगाई गई थीं। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव अभियान के दौरान झालमुड़ी खाई थी, जिससे ममता बनर्जी काफी चिढ़ गई थीं।

इतना विशाल आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद, अब जिम्मेदारी भाजपा पर है कि वह अपने बड़े वादों को सफलतापूर्वक पूरा करे और नई भाजपा सरकार से जनता की जो विशाल अपेक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करे।

तमिलनाडु के संदर्भ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जब स्पष्ट हो गया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, वाजपेयी ने एक उल्लेखनीय भाषण दिया और 13 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेस दलों ने यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया। कांग्रेस, जिसके पास 140 सीटें थीं, ने बाहर से समर्थन देने का विकल्प चुना। यूनाइटेड फ्रंट के पास लगभग 190 सीटें थीं।

कांग्रेस के समर्थन से देवगौड़ा ने बहुमत सुनिश्चित किया और 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले सीताराम केसरी का मानना था कि देवगौड़ा उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं। इस अवधि में कांग्रेस नेताओं से जुड़े पुराने भ्रष्टाचार मामलों की जांच भी तेज हो गई थी। केसरी ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की, जो उन्होंने नहीं किया।

30 मार्च 1997 को केसरी राष्ट्रपति भवन गये और समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया गया और 11 अप्रैल 1997 को यूनाइटेड फ्रंट को 190 वोट मिले, जबकि विपक्ष ने 292 वोट हासिल किए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया।

इसी समय प्रमोद महाजन ने संदर्भित भाषण दिया। महाजन ने अपनी बात शुरू करते हुए रामाकांत खलप के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के चीन दौरे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चीनी प्रतिनिधियों को भारतीय लोकतंत्र के कार्य करने के तरीके को लेकर जिज्ञासा थी, और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने इसे कैसे समझाया।

उन्होंने कहा, "मैं प्रमोद महाजन हूँ। मैं लोकसभा का सदस्य हूँ। मैं सबसे बड़ी पार्टी से हूँ और मैं विपक्ष में हूँ।"

महाजन के अनुसार, चीनी प्रतिनिधियों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने फिर कांग्रेस सांसद श्रीबल्लभ पाणिग्रही की ओर इशारा किया और बताया कि वे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से हैं, जो सरकार के बाहर है, लेकिन सरकार का समर्थन कर रही है। इसके बाद उन्होंने सीपीआई (एम) के एमए बेबी की ओर इशारा किया, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी से हैं, फ्रंट में शामिल हैं, लेकिन सरकार के बाहर हैं।

वीसीके और वामदलों द्वारा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विजय राज्यपाल राजेन्द्र अर्लेकर से मुलाकात कर रहे हैं और यदि उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि टीवीके के पास यथेष्ट संख्या है, तो शपथ लेने का समय तय किया जा सकता है।

अर्लेकर, जो केरल के भी राज्यपाल हैं, लगभग शाम 7 बजे के आसपास राज्य के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उन्होंने वह उड़ान रद्द कर दी। वीसीके का जो समर्थन पत्र एनडीटीवी ने देखा, उसमें कहा गया है कि विजय को समर्थन देने का निर्णय तमिलनाडु में स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। राज्यपाल को संबोधित वीसीके विधायक दल के नेता बन्नी अरसू द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, "डॉ. थोल थिरुमावलवन, टीवीके के अध्यक्ष, हमारे दो विधायकों की ओर से, राज्य में सरकार बनाने के उद्देश्य से टीवीके को उसके अध्यक्ष और विधानक दल के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हमारा समर्थन देते हैं।

यह समर्थन तमिलनाडु के लोगों के लिए स्थिर और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने के हित में दिया जा रहा है। मैं महामहिम से अनुरोध करता हूँ कि कृपया हमारे बिना शर्त समर्थन को रिकॉर्ड पर लें।"

वीसीके प्रमुख थिरुमावलवन ने समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा, "वर्तमान में, हमारा ध्यान केवल एक चीज़ पर है। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए, जहाँ हम विजय सरकार बनाने में असमर्थ रहें। हमें तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू होने नहीं देना चाहिए। इसी आधार पर, बाहर रहकर अपना समर्थन देना सरकार बनाने में सहायता है।"

वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से टीवीके की संख्या में चार महत्वपूर्ण सीटें जुड़ गई हैं। अब इनकी संख्या 120 हो गई है।

जहाँ वाम दलों ने बिना शर्त समर्थन दिया, वहीं कांग्रेस का समर्थन कुछ शर्तों के साथ आया। वाम दलों ने विजय की कैबिनेट से बाहर रहने का निर्णय लिया और, सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस दो मंत्रालयों की उम्मीद कर रही थी।

द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने अपने सहयोगी वीसीके और वाम दलों के विजय को समर्थन देने के निर्णय का स्वागत किया, ताकि सरकार संकट से बच सके।

स्टालिन ने एक वाक्य की पोस्ट में कहा, "मैं हमारे गठबंधन साथियों के इस घोषणा का स्वागत करता हूँ कि वर्तमान संकट से बचने के लिए, यदि हम तमिलनाडु विजय फेडरेशन को सरकार बनाने के लिए समर्थन देते हैं, फिर भी हम नीति के आधार पर डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन में बने रहते हैं।" अपने सहयोगियों की तुलना करते हुए, उन्होंने वीसीके और वाम दलों की "मित्रता की भावना" की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि विजयी कांग्रेस विधायकों ने द्रमुक से, बिना किसी संवाद के, संबंध तोड़ लिए। उन्होंने पहले कांग्रेस द्वारा द्रमुक को छोड़कर टीवीके के साथ जाने के कदम को "पीठ में छुरा घोंपना" कहा था।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहित, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908